Online at: https://researchtrendsjournal.com
Indexed Journal

ISSN No: 2584-282X
Peer Reviewed Journal

INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

Volume 3; Issue 1; 2025; Page No. 176-180

Received: 01-11-2024
Accepted: 05-12-2024

भारतीय औषधि कानूनों में मौजूदा खामियों पर शोध

[1]Manudev and [2]Dr. Vipin Kumar Singh

[1]Research Scholar, Faculty of Law, P.K. University, Shivpuri, Madhya Pradesh, India
[2]Professor, Faculty of Law, P.K. University, Shivpuri, Madhya Pradesh, India

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17459203

Corresponding Author: Manudev

सारांश

मादक द्रव्यों का दुरुपयोग और नशीली दवाओं की लत एक जटिल वैश्विक समस्या है जो समाज के सभी स्तरों के लोगों को प्रभावित करती है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग को कम करने और नशीली दवाओं के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए, दुनिया भर की सरकारों ने विभिन्न नीतियाँ और नियम पारित किए हैं। वैश्विक स्तर पर, नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध तस्करी राष्ट्रीय स्तर पर समाज की स्थिरता, कानून-व्यवस्था और सुरक्षा के लिए बड़े खतरे हैं। यह शोध भारत में नशीली दवाओं के उपयोग के जटिल नेटवर्क की गहराई से पड़ताल करता है और इसके विविध स्वरूप पर प्रकाश डालता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान नियामक ढाँचा, कानून और नीतियाँ, वे सभी कारक हैं जिन पर नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के अध्ययन में विचार किया जाएगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एक सैद्धांतिक पद्धति का उपयोग किया गया, जिसमें एक गुणात्मक दृष्टिकोण और कानूनों, सम्मेलनों, संधियों और नीतियों जैसे महत्वपूर्ण कानूनी स्रोतों की गहन जाँच शामिल है।

मूलशब्द: औषधि, नशीली, मादक भारत, और सामाजिक

प्रस्तावना

भारत जैसे देश में, इसके ऐतिहासिक साहित्य में भांग के इस्तेमाल के कई संदर्भ हैं और वास्तव में, अथर्ववेद (जो कम से कम 2000 साल पुराना है) में भांग के पवित्र होने का संदर्भ है, इसके अलावा ऋग्वेद में भी अमनिता मस्कारिया के अवयवों से तैयार एक पवित्र पेय, 'सोमा' का संदर्भ है। इसी तरह, मेसोपोटामिया (आधुनिक इराक के पास) में चिकित्सा के साथ-साथ मनोरंजक उद्देश्यों के लिए अफीम के इस्तेमाल का पता सुमेरियों तक लगाया जा सकता है, जहां अफीम को हुल गिल कहा जाता था, जिसका मोटे तौर पर अनुवाद 'खुशी का पौधा' होता है। इसी तरह, चीन में भांग के पौधे को कम से कम छठी शताब्दी ईसा पूर्व से जाना जाता है प्री-कोलंबियाई मेक्सिको से भी पेयोट (लोफोफोरा विलियम्सि) के उपयोग के बारे में जानकारी मिली है, जिसका उपयोग लोगों द्वारा 'चेतना की परिवर्तित अवस्था' को सक्रिय करने के लिए किया जाता था।

इसके अलावा, ग्रीक साहित्य में भी 'नेपेंथेस फार्माकोन' का संदर्भ मिलता है; 'नेपेन्थेस फार्माकोन' को एक दुख-निवारक औषधि के रूप में संदर्भित किया जाता है और इसे अफीम का उपयोग करके बनाया जाता है। 11 पहले बताए गए पदार्थों को अक्सर 'एन्थोजेनिक' कहा जाता है जो कि ग्रीक शब्दों 'एन' जिसका अर्थ है 'अंदर', 'थियो' जिसका अर्थ है 'भगवान' और 'जेन' जिसका अर्थ है 'निर्माण करना' से लिया गया है।12 हिंदू पौराणिक कथाओं में, अन्य बातों के अलावा, कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि भांग का पौधा भगवान शिव द्वारा समुद्र से लाया गया था, "जब सभी देवताओं ने इससे "अमृत" निकालने के लिए इसका मंथन किया था।"13 भांग, एक पौधे के रूप में, एशिया में व्यापक प्राकृतिक वितरण रखती है और अन्य स्थानों के अलावा, कैस्पियन सागर (साइबेरिया) के दक्षिण के पास के प्रदेशों में, किर्गिज़ रेगिस्तान (रूसी तुर्किस्तान) में, रूस के मध्य और दक्षिणी भागों में और काकेशस पहाड़ों की निचली ढलानों पर उगती हुई पाई जाती है।

नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी का मुद्दा दुनिया भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करता है। भारत में, 1985 का नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS एक्ट)

नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों को विनियमित करने के लिए प्राथमिक कानूनी ढांचे के रूप में कार्य करता है। अवैध दवाओं के प्रसार के बारे में बढ़ती चिंताओं के जवाब में अधिनियमित, NDPS अधिनियम कानूनी और नियामक उपायों के माध्यम से नशीली दवाओं से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक ठोस प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। यह लेख NDPS अधिनियम का एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है, इसके ऐतिहासिक विकास, प्रमुख प्रावधानों, प्रवर्तन तंत्र और भारत में नशीली दवाओं के नियंत्रण प्रयासों पर प्रभाव की जांच करता है।

नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों का सेवन एक गंभीर समस्या के रूप में उभरा है, जो देश के सामाजिक ताने-बाने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है। युवा पीढ़ी में मादक द्रव्यों के सेवन की महामारी ने भारत में खतरनाक रूप धारण कर लिया है। बदलते सांस्कृतिक मूल्य, बढ़ते आर्थिक तनाव और घटते सहयोगी बंधन मादक द्रव्यों के सेवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुमान के अनुसार मादक द्रव्यों का सेवन लगातार या छिटपुट रूप से किया जाने वाला नशीली दवाओं का सेवन है जो स्वीकार्य चिकित्सा पद्धति के साथ असंगत या असंबंधित है।

साहित्य समीक्षा

मुक्ता. (2021) [1] दुनिया के किसी भी अन्य देश की तरह भारत में भी नशीली दवाओं का दुरुपयोग समाज की ओर से एक कलंक के रूप में सामने आता है, जिसके परिणामस्वरूप नशेड़ी/व्यसनी के मानवाधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मानवाधिकारों की अवधारणा की उत्पत्ति प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत (प्राकृतिक कानून के परिणाम) जितनी ही प्राचीन है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग करने वालों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है क्योंकि पिछले दशक में तीन लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। एनडीपीएस 2 अधिनियम 1985 इसे लागू करते समय पुलिस द्वारा मनमानी की गुंजाइश छोड़ता है। इसलिए, भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली भी इससे अछूती नहीं है और नशीली दवाओं के दुरुपयोग करने वाले इसके शिकार हैं। हालांकि, नव-अपराधशास्त्रियों के दृष्टिकोण में बदलाव देखा गया है जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग को पीड़ितहीन अपराध के रूप में देखने से लेकर मृत्यु, उपेक्षा और हत्या को तत्काल नुकसान के रूप में प्रकट करने की ओर अग्रसर है।

प्रदीप. (2021) [2] अपराध मानवता के समक्ष एक गंभीर समस्या है जो दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। आपराधिक कृत्य पीड़ित, समाज और अंततः पूरी मानवता पर अपरिवर्तनीय और गंभीर प्रभाव डालते हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली को जब प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है, तो ऐसा प्रतीत हो सकता है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में कार्यवाही अपराध होने के बाद ही शुरू की जाती है। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि आपराधिक कानून में पहले से किए गए आपराधिक कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान है। लेकिन आपराधिक न्याय का विस्तृत और उचित विश्लेषण स्पष्ट करता है कि इसका मुख्य उद्देश्य अपराध और अपराधीता की रोकथाम है। अपराध की रोकथाम का अर्थ है अपराध होने से पहले ही प्रारंभिक चरण में कार्यवाही करना। आपराधिक न्याय प्रणाली हमेशा निवारक कार्रवाइयों के लिए महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। अपराध की रोकथाम में पुलिस मुख्य साधन है। उचित और कुशल पुलिस कार्रवाई अपराध और अपराधीता से प्रभावी ढंग से निपटना सुनिश्चित करती है, विशेष रूप से प्रारंभिक चरण में पुलिस कार्रवाई। भारत में, 21वीं सदी में, अपराध और अपराधीता एक गंभीर चुनौती बन रही है; अपराध की प्रकृति अधिक गंभीर होती जा रही है और अपराध दर बढ़ रही है।

गुसलियाना. (2022) [3] मनोविकार नाशक और मादक पदार्थों के वितरण से उत्पन्न धन शोधन अपराधों से निपटने के अपने मिशन के भाग के रूप में, राष्ट्रीय नारकोटिक्स एजेंसी (BNN) ऐसे मामलों की जांच करती है, जो 2010 के UUPPTPPU संख्या 8 के अंतर्गत अपेक्षित हैं। धन शोधन अपराध का एक आवश्यक तत्व नारकोटिक्स अपराध है। विशेष रूप से, यह शोध निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करता है: (क) कौन सी परिस्थितियाँ धन शोधन और मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों से संबंधित कानूनों के प्रवर्तन में बाधा डालती हैं; और (ख) ऐसा कैसे किया जाए। इस तरह के न्यायिक समाजशास्त्रीय अध्ययन का मुख्य केंद्र क्षेत्र अनुसंधान है। जांच का विषय इस बात पर केंद्रित है कि समाज में कानून कैसे लागू किया जाता है, इसलिए समाजशास्त्रीय न्यायिक पद्धति का उपयोग किया जाता है। रिआउ राष्ट्रीय नारकोटिक्स एजेंसी के जासूसों के साथ साक्षात्कार शोधकर्ताओं को यह समझने में मदद करेंगे कि ड्रग आपराधिक कानून प्रवर्तन धन शोधन के आरोपों से कैसे जुड़ा है। इस शोध के परिणामस्वरूप धन शोधन सहित ड्रग अपराधों के लिए कानून प्रवर्तन स्थापित किया गया है, जो BNN जांचकर्ताओं द्वारा इसके कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाएगा।

दीनी. (2024) [4] इस शोध का लक्ष्य संगठनात्मक मूल्यों के साथ संरेखित व्यावसायिकता को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से बेकासी रीजेंसी मेट्रो पुलिस के भीतर समस्याग्रस्त पुलिस कर्मियों के लिए अनुशासनात्मक मार्गदर्शन और कोचिंग का पता लगाना है। गुणात्मक मूल्यांकन का उपयोग करते हुए, अध्ययन इंडोनेशियाई राष्ट्रीय पुलिस सदस्यों के बीच प्रभावी अनुशासन सुनिश्चित करने में व्यावसायिकता के महत्व को प्रकट करता है, इस प्रकार नियमों और अनुशासित पुलिसिंग के पालन को बढ़ावा देता है। अनुशासनात्मक प्रवर्तन ढांचे के रूप में 2003 के सरकारी विनियमन संख्या 2 का उपयोग करते हुए, शोध पुलिस संरचना के भीतर प्रोवोस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कानूनी मानदंडों और अनुशासनात्मक सिद्धांतों को एकीकृत करता है। दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में, अध्ययन नीति संचार, संसाधन आवंटन, स्वभाव और नौकरशाही संरचना में चुनौतियों के कारण समस्याग्रस्त पुलिस कर्मियों को संभालने की अकुशलता को रेखांकित करता है

क्रिसनाफोंग. (2018) [5] अन्य देशों में चलन के अनुरूप रॉयल थाई पुलिस ने स्थानीय संदर्भों के प्रति उत्तरदायी अधिक समुदाय-उन्मुख दृष्टिकोणों की आवश्यकता को स्वीकार किया है। हालाँकि, पुलिसिंग के लिए ऐसे दृष्टिकोणों के विकास में स्थानीय स्तर पर अवैध नशीली दवाओं के उपयोग की प्रतिक्रियाओं को शामिल करने की भी आवश्यकता है, जिसमें नुकसान कम करने की एक व्यापक परिभाषा शामिल होगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य भागीदारों के काम को उनकी पहलों, जैसे कि सुई-विनिमय, में समायोजित किया जाएगा। वर्तमान अध्ययन ऊपरी उत्तर के चियांग माई क्षेत्र में समुदाय-आधारित नशीली दवाओं के उपचार में कानून प्रवर्तन अधिकारियों की भूमिका की जाँच करता है, जिसमें प्रमुख हितधारकों के साथ गहन, गुणात्मक साक्षात्कारों का उपयोग किया जाता है, जिसमें वरिष्ठ पुलिस, न्यायाधीश, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधक, गैर सरकारी कार्यकर्ता और स्थानीय समुदाय के नेता शामिल हैं। अधिकांश साक्षात्कारकर्ताओं ने चिंता व्यक्त की कि स्थानीय समुदायों में नशीली दवाओं के उपयोग को संबोधित करने

के लिए पर्याप्त नहीं किया जा रहा है, और स्थानीय स्तर पर पुलिस द्वारा नुकसान कम करने के दृष्टिकोण को अपनाने में बाधाओं में सरकार द्वारा निर्देशित गिरफ्तारी कोटा और सार्वजनिक स्वास्थ्य भागीदारों के साथ सहकारी रूप से काम करने में अनुभव की कमी शामिल है।

शोध पद्धति

नशीली दवाओं की तस्करी और खपत एक वैश्विक चिंता का विषय है क्योंकि यह सिर्फ़ एक देश तक सीमित नहीं है। दुनिया के एक हिस्से में उत्पादित और उगाई जाने वाली दवाएँ दुनिया के दूसरे हिस्से में बेची, खाई और इस्तेमाल की जाती हैं। भारत और विभिन्न अन्य राज्यों के बीच एक गैर-बाध्यकारी समझौते के रूप में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं नशीली दवाओं के नियंत्रण नीति के कार्यान्वयन और विस्तार के संबंध में मानवाधिकारों का सम्मान। INCB के गठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के नियंत्रण सम्मेलनों के सभी सदस्य देशों को उनके मुख्य उद्देश्य के बारे में याद दिलाना है।

डेटा विश्लेषण

भारतीय नारकोटिक कानूनों की मौजूदा खामियों का विश्लेषण

भारतीय मादक पदार्थ कानून में कमियां

मानवाधिकार विकास कार्यक्रम (एचआरडीपी) के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि "अनिवार्य हिरासत, भले ही इसका कानूनी आधार हो, मनमाना हिरासत भी हो सकती है, जहां यह यादृच्छिक, स्वेच्छाचारी या असंगत हो - अर्थात किसी दिए गए मामले की परिस्थितियों में उचित या आवश्यक न हो और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन्हें केवल नशीली दवाओं के उपयोग या नशीली दवाओं पर निर्भरता के आधार पर हिरासत में न लिया जाए।"338 उन्हें स्वतंत्र सुनवाई का अधिकार होगा और यह समानता के अधिकार से लिया गया है।

नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (ICCPR) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को "दोषी पाए जाने तक निर्दोष माने जाने का अधिकार" तथा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है।

मानवाधिकार परिषद को मानव अधिकार उच्चायुक्त (एचसीएचआर) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कुछ उदाहरणों के साथ इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में मानव अधिकारों का उल्लंघन कैसे हो सकता है, यदि किसी व्यक्ति के पास निर्दिष्ट सीमा से अधिक मात्रा में नशीले पदार्थ पाए गए हों, या उसके पास किसी भवन या वाहन की चाबी हो, तो उसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही में सबूत पेश करने का भार उलट दिया जाए, तथा उसे मादक पदार्थों की तस्करी का दोषी माना जाए।

मानक संचालन प्रक्रिया बनाम परीक्षण प्रक्रिया

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न अवसरों पर एनडीपीएस अधिनियम के कार्यान्वयन पर अपनी चिंता व्यक्त की और मौजूदा स्थितियों का संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों को नोटिस जारी किए और एनडीपीएस अधिनियम के तहत लंबित मुकदमों की स्थिति को सुधारने के लिए, इसने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमों से निपटने के लिए सभी राज्यों को विशिष्ट निर्देश और दिशा-निर्देश जारी किए। इसने अधीनस्थ न्यायालयों को मुकदमे के दौरान अत्यधिक स्थगन देने के खिलाफ भी सख्त चेतावनी दी 349। इसके अलावा, न्यायालय ने सभी राज्यों को एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित मामलों से निपटने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्देश दिया।

भारतीय दण्ड व्यवस्था

भारत ने NDPS मामलों के प्रति दंडात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। जैसा कि भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पिछले कुछ वर्षों के NCRB डेटा से स्पष्ट है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) भारत द्वारा प्रकाशित "भारत में अपराध" नामक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, दोषी ठहराए गए अभियुक्तों की संख्या हर साल लगातार बढ़ रही है और इसलिए NDPS मामलों के तहत दोषसिद्धि दर बहुत अधिक रही है।

तालिका 1: दोषसिद्धि दर

वर्ष	दोषसिद्धि दर	दोषसिद्धि संख्या
2016	74.2	7776
2017	70.6	9637
2018	84.7	9113

उपरोक्त तालिका वर्ष 2016-2018 के दौरान एनडीपीएस अधिनियम के तहत उच्च दोषसिद्धि दर को दर्शाती है। हालांकि एनसीआरबी रिपोर्ट मात्रा के स्तर या तस्करों या ड्रग उपयोगकर्ताओं के आधार पर डेटा को वर्गीकृत नहीं करती है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में एनडीपीएस मामलों की दोषसिद्धि दर विशेष और स्थानीय कानूनों (एसएलएल) की श्रेणी में लगातार सबसे अधिक रही है।

अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य: दण्ड पर

जब हम कानून के शासन के चश्मे से सजा के बारे में सोचते हैं। आनुपातिकता मौलिक सिद्धांतों में से एक प्रतीत होती है और कानून के शासन में निहित है, जिसका उद्देश्य लोगों को किसी भी क्रूर या अमानवीय व्यवहार से बचाना है। दुनिया भर के देशों ने इस सिद्धांत को ज़्यादातर सैद्धांतिक रूप से और कुछ ने टुकड़ों में अपनाया है। नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के लिए इस सिद्धांत को लागू करना मुख्य रूप से विधायकों की ज़िम्मेदारी है। उन्हें कुछ कार्यों के लिए दंड के एक निश्चित स्तर को परिभाषित करना होगा और सामान्य तौर पर, दंड का ऐसा स्तर समाज में दूसरों को होने वाले नुकसान की प्रकृति और स्तर के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

फिर, न्यायालयों और न्यायाधीशों को आनुपातिकता के सिद्धांत को इस तरह से लागू करना चाहिए कि वे प्रत्येक मामले में उचित सजा दे सकें, और अंततः, आनुपातिकता सजा के निष्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

संक्षेप में, आनुपातिकता के सिद्धांत का मुख्य विचार यह है कि किसी व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को केवल उस सीमा तक सीमित किया जाना चाहिए जो किसी वैध उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उचित और आवश्यक हो और इस तरह से कि उनके मौलिक अधिकारों पर कम से कम अतिक्रमण हो।

वैकल्पिक तंत्र - पारंपरिक तरीकों के बजाय सुधार की ओर एक रास्ता दंड: यू.के., अर्जेंटीना और यूरोपीय संघ जैसे देशों में हिंसक अपराधों के लिए दी जाने वाली सज़ाओं की तुलना में नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के लिए सज़ाएँ बहुत ज़्यादा कड़ी हैं। फ्रेमवर्क काउंसिल ने यह भी पाया कि कुछ यूरोपीय संघ

के सदस्यों ने भी नशीली दवाओं के तस्करों पर सख़्त सज़ाएँ लगाई हैं। हालाँकि, अब अपराधीकरण को कम करने की दिशा में बदलाव हो रहा है।

"पुर्तगाल – सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लाभों का एक उत्कृष्ट उदाहरण": वर्ष 2001 में व्यक्तिगत उपभोग के लिए सभी प्रकार की दवाओं के सेवन को अपराधमुक्त करने, तथा पुनर्वास पर अनुकूल नीतियां बनाते हुए 'ड्रग खच्चरों' के लिए सजा कम करने के बाद पुर्तगाल नशीली दवाओं की लत को लगभग आधे तक कम करने में सक्षम हुआ।

वर्ष 2014 में ट्रांसफॉर्म ड्रग पॉलिसी फाउंडेशन (जिसे बाद में टीडीपीएफ के नाम से जाना जाएगा) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार पुर्तगाल ने निजी उपभोग के लिए नशीली दवाओं के उपयोग को अपराधमुक्त कर दिया है। रिपोर्ट को यूएनओडीसी द्वारा पूरक और भरोसेमंद बनाया गया है और यह यूएनओडीसी अभिलेखागार पर उपलब्ध है।

भारत में "ड्रग म्यूल" की अवधारणा नहीं है

यह ध्यान देने योग्य है कि 'ड्रग म्यूल' की अवधारणा को भारतीय वैधानिक कानून में मान्यता नहीं मिली है। 'ड्रग म्यूल' शब्द की कोई एकल परिभाषा नहीं है। हालाँकि, EMCCDA ने अपनी रिपोर्ट में 'ड्रग म्यूल' शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया है: "एक ड्रग कूरियर जिसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार ड्रग्स ले जाने के लिए भुगतान किया जाता है, मजबूर किया जाता है या धोखा दिया जाता है, लेकिन जिसका ड्रग्स में कोई और व्यावसायिक हित नहीं होता है"। ईएमसीसीडीए ने पाया कि आम तौर पर ड्रग खच्चर दो प्रकार के होते हैं और उनके मामलों का फैसला करते समय कम करने वाले कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने 1990 के दशक में पाया कि 'ड्रग खच्चर' तस्कर या 'उपभोक्ता' की बजाय कूरियर की तरह थे। उन्हें बहुत कम मात्रा में ड्रग्स से परिचित कराया जाता था। उन्होंने पाया कि उन पर कठोर दंड लगाने से कोई रोक नहीं थी। उन्होंने पाया कि गरीबी और सामाजिक-आर्थिक कारण अधिक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्तियाँ थीं जिन्होंने लोगों को 'खच्चर' बनने के लिए प्रेरित किया।

वैश्विक मानकों के अनुसार "छोटी मात्रा"

ऐसा लगता है कि भारत में इस मामले में सख्त रुख अपनाया गया है। शोधकर्ता ने अन्य देशों में विभिन्न अपराधों के प्रति व्यवहार की तुलना करने का प्रयास किया है। यूरोपियन मॉनिटरिंग सेंटर फॉर ड्रग्स एंड ड्रग एडिक्शन (EMCDDA) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार यूरोप के आधे से अधिक देश नशीली दवाओं के उपयोग या सेवन को एक विशिष्ट अपराध मानते हैं, हालांकि वे इसमें शामिल मात्रा और दंड में अंतर करते हैं। हालाँकि, कुछ देशों ने अपवाद भी बनाया है। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश मादक पदार्थों की तस्करी के अपराध के लिए तीन साल से अधिक कारावास की सज़ा देते हैं, हालाँकि मादक पदार्थों की तस्करी की उनकी परिभाषा अलग-अलग हो सकती है।

पुनर्वास: वैश्विक मानक और भारत का रुख

यूडीएचआर और मानवाधिकार और ड्रग नीति पर अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देश (एचआरडीपी दिशानिर्देश) 2019 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उच्चतम प्राप्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मानक का आनंद लेने का अधिकार है और यह अधिकार ड्रग कानूनों, नीतियों और प्रथाओं पर भी लागू होता है। एचआरडीपी दिशा-निर्देश प्रत्येक राज्य को संयुक्त राष्ट्र की तकनीकी एजेंसियों, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), एचआईवी/एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम (यूएनएड्स) और यूएनओडीसी द्वारा अनुशंसित हानि न्यूनीकरण सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करते हैं। दिशा-निर्देश राज्यों को कमजोर या हाशिए पर पड़े समूहों के लिए पर्याप्त रूप से धन उपलब्ध कराने और उनके मौलिक अधिकारों (जैसे उचित प्रक्रिया, गोपनीयता, शारीरिक अखंडता सुनिश्चित करना और मनमाने ढंग से हिरासत में न लेना और मानवीय गरिमा बनाए रखना) का पालन करते हुए अलग-अलग प्रावधान करने की भी सिफारिश करते हैं।

राष्ट्रीय सर्वेक्षण से डेटा

प्रश्नावली के अलावा शोधकर्ता ने सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय सर्वेक्षणों से अध्ययन के लिए उपयुक्त आंकड़े एकत्र किए।

तालिका 2: भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याएं- एनसीआरबी

	नशीली दवाओं/शराब की लत के कारण आत्महत्याओं का वर्ष-वार वितरण					
वर्ष	**मामलों**	**पुरुष**	**महिला**	**ट्रांसजेंडर**	**% सत्यापित**	**% आयु**
2016	5199	5097	102	0	41.7	4
2017	6705	6551	152	2	29	5.2
2018	7193	7039	153	1	7.3	5.3
2019	7860	7719	140	1	9.3	5.6
2020	9169	8974	193	2	14.7	6

तालिका 3: नशीली दवाओं/शराब की लत के कारण आत्महत्याओं का आयु-वार वितरण

वर्ष		**18 से नीचे**				**18-30 वर्ष**				**30-45 वर्ष**		
	पुरुष	**महिला**	**ट्रांस-जेंडर**	**कुल**	**पुरुष**	**महिला**	**ट्रांस-जेंडर**	**कुल**	**पुरुष**	**महिला**	**के पारलिंग**	**कुल**
2016	38	5	0	43	1253	19	0	1272	2012	48	0	2060
2017	45	5	0	50	1691	34	1	1726	2631	60	1	2693
2018	46	9	0	55	1745	28	1	1774	2797	64	0	2861
2019	53	3	0	56	1877	31	1	1909	3296	52	0	3348
2020	67	2	0	69	2342	38	2	2382	3568	73	0	3641

नशीली दवाओं/शराब की लत के कारण आत्महत्याओं का आयु-वार वितरण								
वर्ष	45-60				60 वर्ष से अधिक			
	पुरुष	महिला	के पारलिंग	कुल	पुरुष	महिला	के पारलिंग	कुल
2016	1436	26	0	1462	358	4	0	362
2017	1719	40	0	1759	464	13	0	477
2018	1863	45	0	1908	588	7	0	595
2019	1973	42	0	2015	520	12	0	532
2020	2226	62	0	2238	771	18	0	789

तालिका 4: आयु और लिंग के आधार पर एनडीपीएस के तहत गिरफ्तार व्यक्ति

	आयु और लिंग के आधार पर एनडीपीएस के तहत गिरफ्तार व्यक्ति (अपराध शीर्षक के अनुसार)										
	कुल	किशोर पकड़े गए		18-30 वर्ष की आयु		30-45 वर्ष की आयु		45-60 वर्ष		60 वर्ष और उससे अधिक	
वर्ष	गिरफ्तारियां	लड़के	लड़कियाँ	पुरुषों	औरत	पुरुषों	औरत	पुरुषों	औरत	पुरुषों	औरत
2020	83719	272	0	40938	715	30004	1296	9212	542	673	67
2019	95011	247	2	46206	881	33885	1583	10632	670	825	80
2018	81778	227	3	40073	725	29671	1392	8560	559	497	71
2017	78066	209	1	38777	661	28159	1210	7766	572	629	82
2016	59249	191	4	28704	363	21132	924	6806	459	597	69

एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों में गिरफ्तार व्यक्तियों के आयु और लिंग के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह देखा जा सकता है कि गिरफ्तार किए गए अधिकांश व्यक्ति पुरुष वर्ग से हैं और उनकी आयु 28 से 30 वर्ष के बीच है।

निष्कर्ष

भारत में युवाओं में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों का सेवन खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा नशीली दवाओं का उपयोगकर्ता बनता जा रहा है। नशीली दवाओं के उपयोग की सीमा UNODC की 2022 की रिपोर्ट में परिलक्षित होती है, जो अनुमान लगाती है कि दुनिया भर में 284 मिलियन लोग नशीली दवाओं का उपयोग करते हैं। पूर्वी गोल्डन ट्राइंगल और गोल्डन क्रीसेंट के बीच देश का स्थान शोध में उद्धृत एक अन्य कारक है जिसने नशीली दवाओं की समस्या को और बढ़ा दिया है। वैश्विक स्तर पर, नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध तस्करी राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक स्थिरता, कानून और व्यवस्था और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती है। भारत सरकार ने भी कानून का मसौदा तैयार किया है और इसे लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं, लेकिन नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन के मामलों में तेजी से वृद्धि को देखते हुए, ये प्रयास अप्रभावी रहे हैं। भारत में युवाओं में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन का प्रचलन चिंताजनक है।

संदर्भ

1. जांगिड़ M. भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और नशे की लत के शिकार लोगों के मानवाधिकारों के संरक्षण में चुनौतियाँ. 2021.
2. सिंह P. भारत में पुलिसिंग: अपराध और आपराधिकता से निपटने के लिए प्रभावी निवारक कार्रवाई की आवश्यकता. ज मीडिया हुकुम. 2021;28:12624. doi:10.18196/jmh.v28i2.12624.
3. एंड्रीकास्मि S, अर्दिआंतो SA, गुसलियाना B. मनी लॉन्ड्रिंग के साथ कानून प्रवर्तन नारकोटिक्स आपराधिक कार्रवाई का अनुप्रयोग. 2022. doi:10.2991/assehr.k.220406.007.
4. पुत्रा I, हंदयानी R, बिंटारी D. पुलिस सदस्यों का अनुशासनात्मक विकास (बेकासी रीजेंसी मेट्रो पुलिस रेंज के सदस्यों पर केस स्टडी जिन्होंने नारकोटिक्स का उपयोग करने का संकेत दिया). इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीकल्चरल एंड मल्टीरिलिजियस अंडरस्टैंडिंग. 2024;11:518. doi:10.18415/ijmmu.v11i5.5824.
5. पूथाकूल K. समुदाय-आधारित नशीली दवाओं के उपचार में कानून प्रवर्तन की भूमिका और अपराध की रोकथाम पर इसका प्रभाव. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड सोशियोलॉजी. 2018;7:250-259. doi:10.6000/1929-4409.2018.07.18.

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.